

W.A.A. (a)BR(H)-11

सं. प्र.सं. मण्डल, मध्यप्रदेश, खण्डगिरि

दिनांक: 23/09/2023

विषय: मंडार

प्रतिश्री

श्री
जयपुर
मंडार

प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण संहिता की धारा 248 का है जिसमें भूमि शासकीय हानि के नाते विचारण न्यायालय ने सुनवाई के उपरान्त अनाधिकृत आधिपत्य हटाने के 100% अर्थदण्ड के आदेश दिए हैं जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों ने स्थिर रखा है। ऐसी स्थिति में जब भूमि शासकीय है तथा आवेदक का अधिकरण प्रमाणित है तब आवेदकों को कोई अधिकार वैधानिक रूप से आलोच्य भूमि पर नहीं मिलता है। प्रकरण में तीना अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है जिनमें प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः यह निगरानी प्रारंभिक स्तर पर ही अग्रहण की जाती है। आवेदक सूचित हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय का जयपुर में एक प्रमाणित प्रतिलिपि रिकॉर्ड है।

प्रमाणित प्रतिलिपि